

an>

Title: Need to enhance the amount of rent for agricultural land used for laying crude oil pipelines in Sanchore in Jalore Parliamentary Constituency, Rajasthan.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): उपाध्यक्ष मठोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रिश्त रांचौर में केवर्न इंडिया द्वारा वार्षिक एक बीघा जमीन पर 15 छजार रुपये किराया दिया जाता है जो वहां के किसानों के लिए बहुत ही कम है। बाल्मेर जिला में भी प्रत्येक बीघा 15 छजार रुपये किराया है। बाल्मेर जिला में किसान एक साल में एक ही फसल लेते हैं, जबकि रांचौर के किसान रखी और खारीफ की फसल उपजाते हैं। इसलिए यहां के किसानों के खेतों से कच्चे तेल की पाइप लाइन निकालने से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः सांचौर में किसानों के खेतों का किराया 30 छजार से 50 छजार रुपये किराया जाना अति आवश्यक है।

केवर्न बनर्जी द्वारा किसानों से वर्ष 2003 में जमीन किराये पर ली गयी थी। पाइपलाइन बिछाने का कार्य लगभग एक साल से ऊपर चलता रहा। जिन खेतों से पाइप लाइन निकाली गयी वहां और आस-पास फसल नहीं बोने दी गयी, जिसके कारण किसानों को खारीफ एवं रखी की फसलों से वंचित रहना पड़ा। इन खेतों को कम्पनी द्वारा समतल नहीं किया गया, जिससे किसानों को अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में अनेक तर्फ तग गए। कम्पनी द्वारा सड़क के किनारे की जमीन को तीज पर लिया गया है। जिससे अनेक जगहों पर अंदर के खेतों पर जाने का गंतव्य कम्पनी द्वारा नहीं देने के कारण किसानों को अपने खेतों पर जाने में असुविधा होती है। अनेक वर्षों से किसान अपने ही खेतों पर सुनमता से नहीं जा पा रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाए तथा खेतों का किराया जल्द से जल्द बढ़ाया जाए।